हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 37 | लखनऊ | शनिवार 19 सितम्बर 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

राजनाथ ने बंगलूरू में तेजस ट्रेनर और एचटीटी-40 सेना को सौंपे

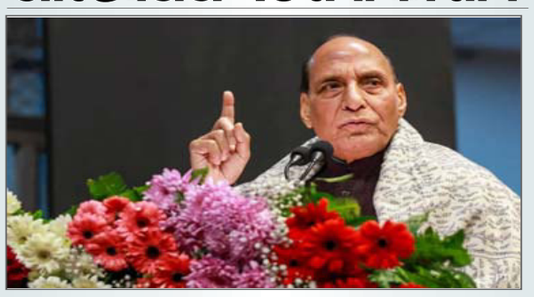

नई दिल्ली,एजेंसी। तेजस एफओसी ट्विन सीटर एक हल्का, हर मौसम में काम करने वाला बहुउद्देश्यीय 4.5 पीढ़ी का विमान है। इसे मुख्य रूप से वायुसेना के पायलट प्रशिक्षण के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें लड़ाकू विमान जैसी संचालन क्षमता भी है। इसमें डिजिटल कॉकपिट, आधुनिक एवियोनिक्स, फ्लाई-बाय-वायर नियंत्रण और कंपोजिट सामग्री से बना ढांचा है। 2010 में 16 तेजस लड़ाकू विमानों और चार ट्विन सीटर का एफओसी अनुबंध हुआ था। सभी 16 लड़ाकू विमान 2022-23 के दौरान दिए जा चुके हैं। अब अंतिम दो ट्विन सीटर की डिलीवरी के साथ यह अनुबंध पूरा हो गया है। इन विमानों में बेहतर रडार, ऑटोपायलट, ईंधन प्रणाली, सुरक्षित संचार और हवा में ईंधन भरने की क्षमता जैसे सुधार भी किए गए हैं। रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल को केवल विमान बनाने वाली संस्था तक सीमित न रखने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि एचएएल में डिजाइन, विकास, निर्माण, प्रमाणन, पूरे जीवनकाल तक रखरखाव और वैश्विक बाजार में बिक्री तक विश्वस्तरीय क्षमता होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने रक्षा परियोजनाओं में होने वाली देरी को गंभीर मुद्दा बताया। उनके अनुसार तकनीकी समेत कई कारणों से परियोजनाओं में देरी होती है और इस पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की समयसीमा ऐसी होनी चाहिए, जो वास्तविक और व्यावहारिक हो, क्योंकि बहुत ज्यादा देरी होने पर तैयार तकनीक हाथ में आने तक पुरानी पड़ सकती है।राजनाथ सिंह ने कहा कि एयरोस्पेस क्षेत्र में अचानक कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। यह एक लंबी और धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। हर उत्पाद और हर पुर्जा इस विकास यात्रा की सीढ़ी का एक कदम है और लगातार इन चरणों को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस लंबी प्रक्रिया में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें विकास की राह में पड़ने वाले पड़ाव के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी हेलीकॉप्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे ओएनजीसी समुद्र में होने वाले संचालन के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि डीजीसीए से प्रमाणित स्वदेशी शक्ति इंजन का एकीकरण भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमता को और मजबूत करता है।

भूजल स्रोतों में यूपी को पहला स्थान पर

योगी सरकार प्रदेशवासियों को भूजल की स्वच्छता सुनिश्चित कर उपलब्ध करा रही शुद्ध पेयजल

लखनऊ,संवाददाता। योगी सरकार प्रदेशवासियों के लिए जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और हर घर तक स्वच्छ व सुरक्षित जल पहुंचाने में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। जांच के अंतर्गत राज्य व जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेशभर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके मुकाबले 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39 प्रतिशत है। 15 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश, देश के राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। यूपी जल निगम

ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भूजल स्रोतों का नियमित परीक्षण पेयजल की गुणवत्ता और जल स्रोतों की स्थिति की निगरानी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी जल स्रोतों की गुणवत्ता, सोर्स सस्टेनेबिलिटी और गहन निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे बेहतर परिणाम हासिल किए हैं और भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा।

पंजाब और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ शीर्ष पर यूपी

भूजल स्रोतों के परीक्षण की राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पंजाब ने निर्धारित लक्ष्य का 83.46 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश ने भी 83.46 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। वहीं उत्तराखंड 82.30 प्रतिशत उपलब्धि के साथ चौथे और केरल 81.13 प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर है।

राष्ट्रीय औसत से करीब 44 प्रतिशत अधिक उपलब्धि

यूपी जल निगम ग्रामीण अधीक्षण अभियंता एवं राज्य प्रयोगशाला प्रमुख ज्ञानेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि भूजल स्रोतों के परीक्षण में उत्तर प्रदेश की 94.39 प्रतिशत उपलब्धि राष्ट्रीय औसत 50.46 प्रतिशत से काफी अधिक है। यानि यूपी ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में करीब 44 प्रतिशत अधिक उपलब्धि दर्ज की है।

आज 818 अभ्यर्थियों को योगी देंगे नियुक्ति पत्र

● लखनऊ,संवाददाता योगी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में शनिवार को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शानिवार को लोकभवन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में चयनित 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, कुल 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 19 सितंबर को आयोजित होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं आयुष विभाग से जुड़े विभागों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के तहत विभिन्न ट्रेडों के अनुदेशक भी शामिल हैं। इस श्रेणी में कुल 48 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें मैकेनिक (ट्रैक्टर), पेंटर (सामान्य), सर्वेयर, मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर गुड्स मेकर, वायरमैन और प्लंबर जैसे पद शामिल हैं। प्लंबर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 31 है, जबकि मैकेनिक (ट्रैक्टर) के छह, वायरमैन के चार और पेंटर (सामान्य) के चार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा सर्वेयर, मैकेनिकल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर गुड्स मेकर के एक-एक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इन नियुक्तियों से विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। वहीं अलग-अलग ट्रेडों में अनुदेशकों की नियुक्ति से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को संबंधित क्षेत्रों में बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के भी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय, कानपुर के तहत सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के नौ पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इन सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों की नियुक्ति से विभागीय स्तर पर आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण और विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित सांख्यिकीय कार्यों को गति मिलेगी।

पंजाबियों को उड़ता पंजाब नहीं उभरता पंजाब चाहिए : नितिन नवीन

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को पठानकोट से पहली नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 'भाजपा का नारा, नशा मिटाना सारा' के संकल्प के साथ शुरू हुई यह नशा मुक्त यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। इस अवसर पर नितिन नवीन ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लडने का आह्वान किया। केसरी दस्तार सजाकर मंच पर पहुंचे नितिन नवीन ने कहा कि पंजाबियों को उड़ता पंजाब नहीं, उभरता पंजाब चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सत्ता के दम पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब करके पंजाब को नशे से बर्बाद किया, उनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लडने का समय आ गया है। नितिन

नवीन ने कहा कि नशा पंजाब की पहचान या ताकत नहीं हो सकता। पंजाब की पहचान उसकी विरासत, विचार और नौजवान होनी चाहिए। पंजाब की पहचान गुरुओं की बाणी, किसानों के पसीने और खिलाडि़यों के जज्बे से होती थी। पंजाब के लोग खुद नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नशे के खिलाफ लड़ाई का मूल मंत्र साझा करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि नशा तस्करों पर वार करना, नशे के सप्लाई नेटवर्क को तोडना, ड्रग मनी जब्त करना, नशे के शिकार लोगों का पुनर्वास करना और समाज के सहयोग से नशे के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाना उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। नितिन नवीन ने कहा कि देश में भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। धारा 370 हटाने के संकल्प को पूरा करने के लिए लंबा संघर्ष किया गया तथा आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म किया गया। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह जुटान कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि हम माताओं-बहनों का दुख बांटने आए हैं।

धर्म को पूजा-पद्धति की सीमाओं से बाहर निकाल कर आचरण में उतारें : भागवत

उज्जैन, (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने युवाओं से धर्म को पूजा-पद्धति की सीमाओं से बाहर निकाल कर जीवन और आचरण से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि धर्म को अंग्रेजी के 'रिलीजन' शब्द का समानार्थी मानना सही नहीं है। 'रिलीजन' का संबंध बांधने और अनुशासन में रखने से है, जबकि धर्म व्यक्ति को मुक्त करता है।डॉ. भागवत ने सेवाङ्ग संस्थानम के तत्वावधान में यहां गीता भवन में आयोजित तीन दिवसीय युवा धर्म संसद में शुक्रवार को कहा कि भारत में धर्म जीवन के हर चरण में मौजूद रहता है। इसे मानें या न मानें, अस्तित्व के आरंभ से अंत तक धर्म बना

रहता है और जीवन के अनेक नियम उसी के अनुरूप चलते हैं।गीता भवन में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित 'युवा धर्म संसद' में देशभर से करीब 1,700 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में शुक्रवार को करीब 300 विद्वान, शिक्षक, शोधकर्ता और धर्माचार्यों ने भी हिस्सा लिया। डॉ. भागवत उद्घाटन सत्र में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके समापन सत्र में 19 सितंबर को शामिल होंगे।संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि मनुष्य जब अपने अहंकार में यह मान बैठता है कि दुनिया उसकी इच्छा और नियंत्रण के अनुसार चलेगी, वहीं से उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। प्रकृति किसी व्यक्ति की सत्ता नहीं मानती और उसके नियम मनुष्य की इच्छा से नहीं बदलते। सूर्य का उदय और अस्त इसका सहज उदाहरण है।उन्होंने कहा कि पश्चिमी समाज ने भारत में धर्म के आचरण, कर्मकांड और अनुशासन को देखा और उसे अपने यहां प्रचलित 'रिलीजन' के समान समझ लिया।

पाक जहाज का रवैया गैर-पेशेवर

भारत-पाकिस्तानी युद्धपोत की टक्कर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत ने शुक्रवार को अरब सागर में भारतीय युद्धपोत और पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज के बीच हुई टक्कर को लेकर इस्लामाबाद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नई दिल्ली ने बुधवार को पाकिस्तान के प्रभारी राजदूत (सीडीए) को तलब कर इस मामले पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था और पाकिस्तानी जहाज के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ी आपत्ति जताई थी।भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात को उस समय घटी जब भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत आईएनएस कोलकाता उत्तरी अरब सागर में एक नियमित निगरानी मिशन और तैनाती पर था। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पीएनएस हुनैन भारतीय युद्धपोत के बेहद करीब आ गया और उसने समुद्र में बेहद गैर-पेशेवर और अस्वीकार्य तरीके से व्यवहार

किया, जिसके चलते दोनों जहाजों में टक्कर हो गई।ष्इसके बाद भारत के विरोध पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने मनगढ़ंत आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि यह टक्कर पाकिस्तान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में भारतीय जहाज की उकसावे वाली और अस्वीकार्य कार्रवाई की वजह से हुई। इन आरोपों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के जवाब को देखा है और यह उसकी पुरानी बहानेबाजी और टालमटोल की आदत ही है। भारत पाकिस्तान के इन सभी आरोपों और आक्षेपों को पूरी तरह नकारता है।रणधीर जायसवाल ने बताया कि आईएनएस कोलकाता पश्चिमी अरब सागर में एक सामान्य गश्त पर तैनात था। इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस हुनैन ने समुद्र में बेहद गैर-जिम्मेदाराना और गैर-पेशेवर व्यवहार दिखाया। पाकिस्तानी जहाज ने खतरनाक तरीके से आगे निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई।

प्रधानमंत्री मोदी आज 51 हजार से अधिक युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को 20वें रोजगार मेले के दौरान विभिन्न सरकारी संगठनों में नवनियुक्त 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, रोजगार मेले का आयोजन देशभर में 45 स्थानों पर किया जाएगा। इस दौरान नियुक्त होने वाले युवा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। इनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय सहित अन्य विभाग शामिल हैं। सरकार के अनुसार, रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें देश के विकास में अधिक भागीदारी का अवसर देने की दिशा में निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

नीट परीक्षा: अब तैयारियों को परखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज

नई दिल्ली,एजेंसी। नीट पेपर लीक की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेंच के जज खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अपग्रेड की गई सुविधाओं का दौरा कर सिस्टम की तैयारियों को देख सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा कराने वाली एनटीए ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए काम करने के तरीके में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में किए गए बदलाव शामिल हैं।जस्टिस नरसिम्हा ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह और जस्टिस अराधे सिस्टम की जांच करने के लिए एनटीए की नई अपग्रेड की गई सुविधा का दौरा करना चाहेंगे।पेपर लीक की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए ह्ड्ड के

सिस्टम को संस्थागत रूप से मजबूत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ तुरंत या अस्थायी उपाय काफी नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि पूरे सिस्टम का स्थायी होना ही मुख्य बात है। बेंच ने मेहता से कहा एक स्थायी सेटअप, स्थायी स्टाफ और स्थायी विभाग होने चाहिए। डेपुटेशन (प्रतिनियुक्ति) बहुत कम होनी चाहिए। तभी एक स्थायी ढांचा तैयार हो पाएगा।÷जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि जज दिल्ली में मिंटो रोड स्थित एनटीए ऑफिस जाएंगे और देखेंगे कि सिस्टम असल में काम कर रहा है या नहीं, साथ ही वहां के मैनपावर और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। शुरुआत में केंद्र ने बेंच को बताया कि नीट में संरचनात्मक सुधारों का सुझाव देने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई-पावर्ड पैनल ने व्यापक विचार-विमर्श किया है । और इस महीने के आखिर तक अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंपने की संभावना है। मेहता ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के सुझाव पैनल के सामने रखे गए थे, जिसने पूर्व ढ्ढस्ह्र चेयरमैन च् राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पिछली कमेटी के सदस्यों के साथ भी विचार-विमर्श किया था।

जनसुनवाई और जन-विश्वास शिविर बड़ी योजनाओं जितने ही महत्वपूर्णः सिंधिया

गुना। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर शुक्रवार प्रदेश के सभी जिलों में शासन-प्रशासन द्वारा ''सेवा ही संकल्प'' की भावना के साथ जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। जनसुनवाई और जन-विश्वास शिविर बड़ी योजनाओं जितने ही महत्वपूर्ण हैं। प्राप्त आवेदनों का गंभीरता और तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गुना जिले के प्रवास के दौरान ''मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान'' के अंतर्गत बरखेड़ागिर्द में आयोजित शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ड्रोन दीदी के माध्यम से आधुनिक तकनीक आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। किरण द्वारा ड्रोन संचालन का प्रदर्शन इसका उदाहरण है।

गुजरात से अरुणाचल तक बारिश-आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में मॉनसून की विदाई का समय शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह साफहोने वाला नहीं है। प्डक् के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में कई मौसमी सिस्टम सक्रिय रहेंगे, जिनके कारण गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक अलग-अलग इलाकों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर थाईलैंड के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण 18 सितंबर की शाम तक उत्तर अंडमान सागर में पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से 19 सितंबर की शाम तक यहां कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह सिस्टम अगले तीन-चार दिनों में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तट की ओर जा सकता है। इसके चलते ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत आसपास के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बिहार में 18 से 24 सितंबर तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 18 सितंबर को कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड में 18 से 23 सितंबर तक बारिश और 24 सितंबर को व्यापक बारिश के आसार हैं। ओडिशा में 18 और 23 सितंबर को भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल में 20 और 23 सितंबर को बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात के आसपास निचले क्षोभमंडल में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और आंधी-तूफान की संभावना है।

टीएमसी में टूट के बाद दोनों गुटों को मिला नया नाम-चिह्न

ममता खेमे को एमएआईटीसी और फुटबॉल खिलाड़ी का सिंबल

नई दिल्ली(एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में संगठनात्मक विवाद के बीच चुनाव आयोग ने आगामी उपचुनावों के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' (एमएआईटीसी) नाम और 'फुटबॉल खिलाड़ी' चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं ऋ्रब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और 'लिफाफा' चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। आयोग की यह व्यवस्था फिलहाल आगामी उपचुनावों के लिए अंतरिम है। पार्टी के मूल नाम 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' और उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह 'दो फूल और घास' पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दोनों पक्षों ने वैकल्पिक नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों की अपनी प्राथमिकताएं आयोग को भेजी थीं। इसके आधार पर ममता बनर्जी गुट को एमएआईटीसी नाम के साथ फुटबॉल खिलाड़ी का प्रतीक मिला है। ऋ्रब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' नाम और लिफाफा चुनाव चिन्ह दिया गया है। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल के साथ मेघालय और त्रिपुरा में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दर्ज किए जाने की व्यवस्था की गई है। ममता बनर्जी गुट ने आयोग को तीन वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्हों के विकल्प भेजे थे। इनमें 'ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस', 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता' और 'तृणमूल ममता कांग्रेस'

जैसे नाम शामिल थे। सिंबल के विकल्पों में फुटबॉल, प्रार्थना और क्रिकेट बैट दिए गए थे। क्रिकेट बैट के साथ 'खेला होबे' का नारा भी प्रस्तावित किया गया था। आयोग को ये विकल्प ईमेल के माध्यम से भेजे गए थे। ऋ्रब्रत बनर्जी ने भी आयोग के निर्देश के मुताबिक वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्हों की सूची भेजी थी। उनके गुट की ओर से 'राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस' और 'लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस' जैसे नाम सुझाए गए थे। मुक्त प्रतीकों में ब्लैकबोर्ड, लिफाफा और टॉर्च को विकल्प के तौर पर रखा गया था। आयोग के अंतरिम फैसले के बाद ऋ्रब्रत गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफा प्रतीक मिला है। दिए गए विवरण के अनुसार, विवाद की जड़ पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और नेशनल वर्किंग कमेटी के कार्यकाल से जुड़े दावों में है। ऋ्रब्रत गुट का दावा है कि पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी का गठन फरवरी 2022 में हुआ था और उसका तीन साल का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त हो गया। इस आधार पर गुट ने मौजूदा संगठनात्मक ढांचे की वैधता पर सवाल उठाए। इसी विवाद के बीच 22 जून 2026 को बागी नेताओं की एक बैठक हुई। ऋ्रब्रत गुट का दावा है कि इस बैठक में अरूप रॉय को नेशनल वर्किंग कमेटी का चेयरपर्सन चुना गया। इसके बाद इस गुट ने चुनाव आयोग के समक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। ममता बनर्जी गुट ने बागी पक्ष के दावों को स्वीकार नहीं किया।

अमेरिका की नई पैंतरेबाजी से डरने की जरूरत नहीं

ललित गर्ग
****

विश्व राजनीति में शक्ति केवल सैन्य क्षमता या आर्थिक आकार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि कोई महाशक्ति अपने प्रभाव का इस्तेमाल किस प्रकार करती है। आज अमेरिका की व्यापार एवं प्रतिबंध नीति इसी कसौटी पर बहस के केंद्र में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंधों को विदेश नीति के प्रमुख उपकरणों के रूप में अधिक आक्रामक ढंग से इस्तेमाल किया है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर संभावित 100 प्रतिशत तक टैरिफ का अधिकार देने वाला नया अमेरिकी विधेयक इसी बदलते रुख का ताजा उदाहरण है, लेकिन इस नये बिल के जरिये वह भारत पर दबाव नहीं बना सकता। भारत को इससे डरने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि नई बन रही विश्व-संरचना में यह बिल अधिक प्रभावी नहीं बन सकेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर 2026 को यह विधेयक पारित किया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि 100 प्रतिशत टैरिफ स्वतः लागू नहीं हुआ है, विधेयक राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देता है। भारत के संदर्भ में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस भारत के ऊर्जा आयात का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। अगस्त 2026 में भारत रूस से लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात कर रहा था। ऐसे में यदि अमेरिकी राष्ट्रपति इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सीधा असर भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ सकता है और साथ ही भारत की ऊर्जा लागत पर भी दबाव बन सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यहीं से असली सवाल उठता है-क्या व्यापारिक टैरिफ अब केवल व्यापार संतुलन सुधारने का साधन रह गए हैं या वे विदेश नीति को मनवाने का माध्यम भी बनते जा रहे हैं? अमेरिका और भारत के बीच व्यापार छोटा नहीं है। 2025 में दोनों देशों का वस्तु एवं सेवा व्यापार लगभग 239.6 अरब डॉलर रहा और अमेरिकी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने भारत से 103.8 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात की। इसलिए किसी बड़े अतिरिक्त टैरिफ का असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा, अमेरिकी आयातकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों की कंपनियों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती दोहरी है। पहली चुनौती अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने की है और दूसरी ऊर्जा सुरक्षा की। यदि रूसी तेल पर निर्भरता अचानक घटानी पड़े तो भारत को वैकल्पिक स्रोतों से महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में पहले से मौजूद अस्थिरता ऐसी स्थिति को और जटिल बना सकती है। दूसरी ओर अमेरिका को भी यह देखना होगा कि अत्यधिक टैरिफ से वैश्विक तेल आपूर्ति, कीमतों और अपने सहयोगी देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मौजूदा कानून में राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रीय हित के आधार पर छूट की गुंजाइश भी रखी गई है। भारत की प्रतिक्रिया का महत्व यहीं बढ़ जाता है। भारत ने न तो किसी शक्ति-गुट के साथ अपने संबंध समाप्त करने की नीति अपनाई है और न ही अपने आर्थिक हितों को किसी एक देश की प्राथमिकताओं के अधीन करने की बात कही है। भारत का घोषित दृष्टिकोण ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना है। यही रणनीतिक स्वायत्तता बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बन सकती है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली में हाल में संपन्न 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखना उपयोगी होगा। भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में 11 सदस्य देशों ने 140-बिंदु नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया। ब्रिक्स ने सीमा-पार भुगतान को अधिक सुगम बनाने तथा सदस्य देशों की स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक निपटान की संभावनाओं पर आगे काम करने का समर्थन किया। साथ ही भारत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी साझा ब्रिक्स मुद्रा का प्रस्ताव नहीं है। यह अंतर समझना बेहद जरूरी है। दुनिया तत्काल डॉलर को हटाकर कोई नई वैश्विक मुद्रा स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। डॉलर अभी भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में अत्यंत प्रभावशाली है। लेकिन यदि अनेक देश धीरे-धीरे द्विपक्षीय व्यापार में अपनी-अपनी मुद्राओं का उपयोग बढ़ाते हैं, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां विकसित करते हैं और डॉलर पर निर्भरता कम करने के रास्ते तलाशते हैं, तो लंबे समय में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय हो सकती है। विशेषज्ञ विश्लेषण भी यही संकेत देता है कि डॉलर से दूरी की प्रक्रिया अभी धीमी और क्रमिक है, न कि कोई तत्काल बदलाव। भारत-रूस संबंध इसका एक व्यावहारिक उदाहरण हैं। सितंबर 2026 में रूसी पक्ष ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा अब रुपये और रूबल में निपटाया जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिबंधों और भुगतान संबंधी बाधाओं के बीच वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ब्रिक्स की दिशा को इसलिए अमेरिका-विरोधी संगठन के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। नई दिल्ली घोषणा का मूल जोर आर्थिक सहयोग, व्यापार, भुगतान व्यवस्था, विकास और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार पर है। भारत के लिए इसका महत्व इस बात में है कि वह पश्चिम और गैर-पश्चिम दोनों आर्थिक शक्तियों के साथ संवाद रखते हुए अपने लिए अधिक विकल्प तैयार कर सके। 2025-26 में भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार 417 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान भी इस समूह के बढ़ते आर्थिक महत्व को दर्शाता है। अमेरिका की वर्तमान नीति का सबसे गंभीर प्रभाव शायद टैरिफ से भी आगे जाकर विश्वास और नीति-पूर्वानुमेयता पर पड़ सकता है। जब व्यापारिक शुल्क बार-बार विदेश नीति के दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तो अन्य देश स्वाभाविक रूप से वैकल्पिक बाजार, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां खोजने लगते हैं। यह प्रक्रिया अमेरिका को तत्काल कमजोर कर देगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगीय लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि ऐसी नीतियां दूसरे देशों को जोखिम कम करने के लिए नए विकल्प तलाशने का प्रोत्साहन देती हैं। भारत के लिए यह समय प्रतिक्रिया की राजनीति से आगे बढ़कर रणनीतिक तैयारी का है। अमेरिकी बाजार भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यापार वार्ता और संवाद के रास्ते खुले रखना आवश्यक है। साथ ही यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, आसियान, रूस और ब्रिक्स देशों में बाजारों का विस्तार, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण भी उतना ही जरूरी है। भारत की ताकत किसी एक ध्रुव से दूरी बनाने में नहीं, बल्कि अनेक ध्रुवों के बीच अपने हितों के लिए पर्याप्त विकल्प बनाए रखने में है। आज की दुनिया 1990 के दशक जैसी एकध्रुवीय व्यवस्था नहीं रही। चीन का आर्थिक विस्तार, भारत का बढ़ता बाजार, रूस की ऊर्जा क्षमता, पश्चिम एशिया की रणनीतिक भूमिका और ग्लोबल साउथ की बढ़ती सामूहिक आवाज विश्व व्यवस्था को नया आकार दे रही है। ऐसे समय में किसी भी महाशक्ति के लिए दूसरे देशों पर लगातार दबाव डालकर अपनी प्राथमिकताएं मनवाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है। भारत की हालिया ब्रिक्स अध्यक्षता ने यह संदेश जरूर दिया है कि भारत टकराव के बजाय संवाद, सहयोग और बहुपक्षीय विकल्पों को महत्व देता है।

संम्पादकीय

सुविधा का लेन-देन

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई देश में लेन-देन के एक लोकप्रिय और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित हुआ है। इससे भी बढ़कर भारत की निरंतर डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में दो हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर चार्जेज कारोबारियों के ऊपर लगाने की बात कही गई है। इस घोषणा ने सरल-सुलभ लेन-देन करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के मन में कई सवालों को जन्म दिया है। हालांकि, राहतकारी यह है कि नोटिफिकेशन में दो हजार तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर कोई शुल्क न लगाने की बात कही गई है। लेकिन इससे देश में अधिक मूल्य वाले यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर चार्जेज लगाने का रास्ता खुल गया है। बैंकों, सेवा प्रदाता संस्थाओं व विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधि जल्द ही दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क निर्धारण करेंगे। निस्संदेह किसी भी बेहतर सुविधा के लिए उपभोक्ता की भी आर्थिक जवाबदेही बनती है। उल्लेखनीय है कि साल 2016-17 में महज 0.07 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन मूल्य से यूपीआई के जरिये 314 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। वैसे आम उपभोक्ता पर सीधे तौर पर एमडीआर लगने का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में 96 फीसदी लेन-देन दो हजार रुपये की सीमा में ही आता है। लेकिन यदि कारोबारियों पर दो हजार से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर शुल्क लगता है तो येन-केन-प्रकारेण वे इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का ही प्रयास करेंगे। वास्तव में आज जब साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार अप्रत्याशित तेजी आ रही है तो हर रोज होने वाले करोड़ों डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा करना भी जरूरी हो जाता है। विशेषकर, छोटे विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। निस्संदेह, सरकार का यह तर्क वाजिब है कि इतने बड़े इकोसिस्टम को हमेशा सरकारी अनुदान के भरोसे नहीं चलाया जा सकता है। यह भी हकीकत है कि सरकार को यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लागू इसलिये करना पड़ा क्योंकि यूपीआई नेटवर्क चलाने के लिए हर साल बीस हजार करोड़ का बोझ उसे वहन करना पड़ता है। पहले सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक व पेमेंट लेने वाले व्यापारियों पर कोई फीस नहीं लगायी थी। लेकिन यूपीआई नेटवर्क के विस्तार के साथ इसे चलाने का खर्च भी लगातार बढ़ता चला गया। यूपीआई का कितनी तेजी से विस्तार हुआ, इस बात का पता इस आंकड़े से चलता है कि वर्ष 2026 के वित्तीय वर्ष में यूपीआई के जरिये हुए 24,161. 69 करोड़ लेन-देन 314 लाख करोड़ रुपये कीमत के हुए। इस बीच यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 44 से बढ़कर 703 हो गई है। देश में करीब 55 करोड़ लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। निर्विवाद रूप से आज के दौर में साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के लिए लगातार नये निवेश करने की जरूरत होती है। ऐसे में दो हजार से अधिक मूल्य के व्यापारिक लेन-देन पर सीमित मात्रा में एमडीआर मॉडल बैंकों और भुगतान प्रदाताओं के लिए एक स्थायी राजस्व का तंत्र विकसित कर सकता है।

एआई से खतरों के बीच मुनाफे और ताकत के दांव

राजेश पांडेय
****

इन दिनों दुनियाभर खासकर अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली तबाही पर गर्म बहस छिड़ गई है। विश्व के भविष्य को लंबे समय तक प्रभावित करने वाली तकनीक में दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन के साथ दिग्गज टेक्नालॉजी कंपनियों के बड़े दांव लगे हैं। एआई से मानवता के अस्तित्व को खतरों की चेतावनियों के बावजूद कोई पक्ष पीछे नहीं हटना चाहता है। अमेरिका, चीन को अपना प्रभाव कम होने और पिछड़ने की आशंका है तो टेक कंपनियों की नजर अरबों रुपए के निवेश और मुनाफे पर है। इस रस्साकशी ने उम्मीद जगाई है कि देर-सबेर एआई पर काबू पा लिया जाएगा। एआई या कृत्रिम बुद्धि के विध्वंसक नतीजों के बारे में एआई के गॉडफॉदर माने जाने वाले वैज्ञानिक ही आगाह कर रहे हैं। यहां कुछ नामी साइंटिस्ट का जिक्र काफी होगा। मांट्रियल यूनिवर्सिटी, कनाडा में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जोशुआ बेंजिओ 2023 से एआई के कारण मानव अस्तित्व को खतरे और उस पर मानवीय नियंत्रण खत्म होने के बारे में कह रहे हैं। बेंजिओ ने एआई के खिलाफ अभियान छेड़ने और सुरक्षा का सिस्टम बनाने के लिए लॉ जीरो संगठन बनाया है। लॉ जीरो बेकाबू एआई एजेंट को बेअसर करने के सेफ्टी सिस्टम बना रहा है। संगठन को जर्मनी और कनाडा की सरकारों के साथ माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया से मदद मिली है। बेंजिओ के साथ 2018 में एलन ट्यूरिंग पुरस्कार हासिल करने वाले ज्याफ्रेहिंटन ने 2023 में गूगल से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना

था कि वे एआई के जोखिमों पर अधिक स्वतंत्रता से बोलने के लिए काम छोड़ रहे हैं। हिंटन कहते हैं कि एआई मानवों से अधिक स्मार्ट हो जाएगी और सत्ता पर कब्जा करने जैसे लक्ष्य बना लेगी। उसे बंद करना या नियंत्रण में रखना असंभव हो जाएगा। गूगल के पूर्व शोधकर्ता का कहना है कि एआई का बुरे लोग दुरुपयोग करेंगे,ऑटो साइबर हमले होंगे और जैविक वायरस तैयार किए जाएंगे हैं। वे इस टेक्नालॉजी के कारण बेरोजगारी बढ़ने और चुनावों में धांधली का अंदेशा भी जताते हैं। बेंजिओ, हिंटन के साथ एआई लैब्स में काम करने वाले कई शोधकर्ता लगातार चिंता जता रहे हैं। वे कहते हैं कि एआई इस दशक के अंत तक मानवों का अस्तित्व खत्म कर देगी। इनकी चेतावनियों ने वैसा असर नहीं किया है जैसा कि 8 सितंबर को एआई लैब एंथ्रोपिक से जेकब कॉक्सन के इस्तीफे का हुआ है। कॉक्सन ने तीन साल तक ओपनएआई और एंथ्रोपिक में एआई के शक्तिशाली मॉडलों को प्रशिक्षित किया है। उनके इस्तीफे की पोस्ट को इंटरनेट पर 24 घंटे से कम समय से नौ करोड़ से अधिक व्यू मिले थे। उन्होंने सबसे बड़ा खतरा बताया यह है कि यदि हमने एआई की वर्तमान गति को धीमा नहीं किया तो निकट भविष्य में हम सब मर जाएंगे। वे कहते हैं, एआई कंपनियों में काम कर रहे सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं। कॉक्सन की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। 12 सितंबर को एंथ्रोपिक के प्रमुख डैरियो अमोडेई ने एक लेख में सुझाव दिया है कि एआई पर सामूहिक रोक और संयम की जरूरत है। प्रमुख एआई लैब्स को एआई की क्षमता बेहतर बनाने की गति धीमी करना चाहिए। ओपनएआई के सैम आल्टमैन, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्सएआई के मालिक एलन मस्क का भी कहना है कि एआई मॉडलों की रफ्तार धीमी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला कहते हैं, एआई के बड़े मॉडलों को समाज की मदद और मानवीय नियंत्रण के सिद्धांतों से निर्देशित होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे कीमती टेक कंपनी एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग कहते हैं, एआई को नियंत्रित करने के लिए किसी नए कानून या नियमों की जरूरत नहीं है। उनका कहना है, नियंत्रण का काम बाजार की ताकतें करेंगी। हुआंग जोर देते हैं, तेजी से आगे बढ़ें लेकिन अगर किसी बिंदु पर लगता है कि कंपनी या उसके प्रोडक्ट काबू से बाहर जा रहे हैं तो ठहर जाइए और सुधार कीजिए। कुछ टेक्नालॉजी कंपनियां एआई की गति को धीमी करने की बात तो करती हैं लेकिन वे निर्णायक कदम नहीं उठा रही हैं। दरअसल, उनका मुनाफा और बाजार मूल्य एआई पर बहुत हद तक निर्भर है। अलग-अलग कंपनियों ने सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया और एआई मॉडलों के दम पर अरबों रुपए कमाए हैं। इनका बाजार मूल्य कई देशों के जीडीपी से आगे है। इस समय एनवीडिया का बाजार मूल्य 5.35 लाख करोड़ रुपए, एपल 450 लाख करोड़ रुपए, गूगल 393 लाख करोड़ रुपए, माइक्रोसॉफ्ट 355 लाख करोड़ रुपए, अमेजन 266 लाख करोड़ रुपए और मेटा का मूल्य 158 लाख करोड़ रुपए है। बड़ी टेक कंपनियां एआई पर काफी पैसा लगा रही हैं। अमेजन, गूगल, फेसबुक की मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने 2024-25 और 2025-26 में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजी खर्च के बतौर 95 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और जापान के सॉफ्ट बैंक ने निवेश किया है। लिहाजा,उनके लिए यह काम समेटना या धीमा करना मुश्किल नहीं है लेकिन कारोबार की होड़ उनके कदम रोकती है। निवेशक भी खुले हाथ से पैसा लगा रहे हैं। 2020 में निवेशकों ने रोबोटिक्स, स्पेस, क्वांटम कंप्यूटिंग में 2.1 लाख करोड़ रुपए लगाए थे। 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये सभी तकनीक एआई से जुड़ी हैं। एआई की होड़ देशों और कंपनियों के बीच टेक्नालॉजी के कारण बढ़ती असमानता पर भी रोशनी डालती है। एआई में भारत सहित कई देशों की कंपनियां निवेश कर रही हैं। लेकिन, वे इनोवेशन में पीछे हैं। केवल फ्रांस की मिस्ट्रल अमेरिकी, चीनी कंपनियों का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती है। इसी तरह एआई में बड़ी कंपनियों को ज्यादा कामयाबी मिली है। ओपनएआई और एंथ्रोपिक का आकार छोटा है पर वे इनोवेशन में अव्वल हैं। चीन की अलीबाबा, डीपसीक और जेडएआई जैसी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों के मुकाबले कम खर्च में एआई मॉडल बना रही हैं। एआई से साइंस, टेक्नालॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती जैसे क्षेत्रों में असीमित संभावनाओं के साथ देशों की सामरिक ताकत भी जुड़ी है। इसलिए अमेरिका, चीन की सरकारें रोक लगाने के विचार का सख्त विरोध कर रही हैं। टेक्नालॉजी से मानव की तरक्की से कोई इन्कार नहीं करता है। लेकिन उसके दुरुपयोग की आशंकाओं को खारिज भी नहीं कर सकते हैं। एआई को किनारे रख दें और सोशल मीडिया के प्रभाव को देख लें तो स्थिति समझी जा सकती है। सोशल मीडिया की लत युवाओं, किशोरों के साथ सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रही है। लेकिन, उस पर कारगर रोक किसी कंपनी ने नहीं लगाई है। कुछ सरकारों ने जरूर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की पहल की है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम आयु के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर कई तरह के नियंत्रण लगाए हैं। कुछ अन्य देश ऑस्ट्रेलिया के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कंपनियों ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। सोशल मीडिया के अनुभव को देखते हुए टेक कंपनियों से अपनी तरफ से एआई पर पूरी तरह रोक लगाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

आज का राशिफल

निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।

आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।

बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।

नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।

महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।

किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।

मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरें के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।

विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सनिध्य प्राप्त होगा।

आवेश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

भारतवंशी चीतों की बढ़ती संख्या

सर्वमित्रा सुरजन
****

दुर्लभ चीता परियोजना की सफलता अंततः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की देन है। मोदी देश ही नहीं दुनिया के ऐसे विरल सोच वाले नेता हैं, जो एक साथ अनेक विषयों पर सोचने के साथ क्रियान्वयन तो करते ही हैं, प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भी उनके सोच के दायरे में। देश में चीता पुनर्वास परियोजना उनकी इसी दृष्टि का एक सफल कीर्तिमान है। मध्यप्रदेश जिले के श्योपुर जिले में स्थित कूनो आभ्यारण्य की धरती पर अफ्रीका से लाए चीतों का पालन-पोषण चार साल पहले आरंभ हुआ था, जो अब एक बड़े भारतवंशी चीतों के कुल में बदल गया है। अफ्रीका से लाए चीतों के जीवित रहने की दर अनुमान से ज्यादा बेहतर रही। इसी का परिणाम है कि भारत में जन्म लेने वाले चीता शावकों का वंश लगातार बढ़ रहा है। कूनो में जन्मी मादा चीताएं अनेक बार मां बन चुकी हैं। इनसे जन्मे 19 शावक पूरी तरह स्वास्थ्य रहते हुए जंगली बाड़े में नटखट अठखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। मानवीय निगरानी के बीच इनकी वृद्धि शत-प्रतिशत आंकी गई है। मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को कूनो में नमीबियाई चीतों को छोड़ने के साथ इनके पुनर्वास की पहल हुई थी। वर्तमान में यहां चार मादाओं के 19 शावक उछलकूद मचाए हुए हैं। भारत की धरती पर अब तक 49 चीतों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 32 जीवित हैं। यानी कूनो में चीतों के जीवित रहने की दर 65.3 प्रतिशत है, जबकि इनके मूल निवास स्थल अफ्रीकी जंगलों में प्राकृतिक रूप से महज 5 से 10 प्रतिशत शावक ही व्यस्क होने का सुख भोग पाते हैं। यहां ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वनकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। दरअसल, कूनो का प्रबंधन बाहरी हस्तक्षेप से लगभग मुक्त है। इसीलिए यह वन प्रांत अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों के वंश के महाद्वीप में बदलता जा रहा है। यहां के वातावरण से अफ्रीका के वातावरण को भिन्न एवं प्रतिकूल माना जा रहा था, किंतु अब चीतों की संख्या में वृद्धि ने जता दिया है कि कूनो के जंगल का परिवेश इन चीतों के रहवास हेतु अनुकूलन रच रहा है। यह प्रकृति की ही देन हैं। प्रदेश के जंगलों में बाघ, तेंदुए और स्याहगोश तो पूर्व से ही हैं, अब बिल्ली प्रजाति का चीता भी यहां के आभ्यारण्यों में देखा जाने लगा है। प्रदेश के ही गांधी सागर आभ्यारण्य में भी चीते छोड़े गए हैं लेकिन यहां इनकी फिलहाल वंशवृद्धि शुरू नहीं हुई है।

हालांकि चीता शावकों के जन्म को लेकर यह विडंबना देखने में आ रही है कि जो चीते बाड़े में जन्म लेते हैं, उनके जीवित रहने की दर तो उत्तम है, किंतु खुले जंगल में जन्मे ज्यादातर चीते जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। कूनो में जन्मी मादा केजीपी-12 ने 11 अप्रैल 2026 को खुले जंगल में चार शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा था। यह भारत में जन्मी किसी मादा द्वारा वन में प्राकृतिक प्रसव का पहला मामला था लेकिन एक महीने के भीतर 12 मई को चारों शावक मृत पाए गए। इसके बाद छह जून को इनकी मां का भी निधन हो गया। ये मौतें कैसे हुईं, यह रहस्य ही बना हुआ है। नमीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए थे। नई धरती और जलवायु परिवर्तन के चलते इन चीतों को आरंभ में यहां के मौसम से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आईं। नतीजतन छह वयस्क और यहीं पैदा हुए चार शावकों में से तीन की मौतें भी हुईं थीं, इस कारण परियोजना पर सवाल भी खड़े किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी 2024 को दो साल पूरे हो हुए थे, इस अवधि में इन चीतों की मृत्यु दर में कमी ने परियोजना की सफलता के प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इनकी जीवित रहने की दर शुरुआत में नमीबिया से लाए चीतों से बेहतर रही थी। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों में से 33.3 प्रतिशत की मौत हुई, जबकि नमीबिया से लाए गए चीतों में से 37.5 प्रतिशत चीतों की मौत हुई। अफ्रीका से लाई गई तीन मादा चीताओं ने अब तक 12 शावकों को जन्म दिया, जो भारतीय परिवेश में पलते एवं बढ़ते चले गए। इन्होंने ही नए घर कूनो में आबादी बढ़ाने की शुरूआत की थी। नए आवास स्थलों में 50 फीसदी चीतों की मौत को सामान्य माना जाता है। एक समय था जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की शान हुआ करती थी लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया था। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देयदृष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नमीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुर्तीली नस्ल की संख्या बढ़ाई नहीं जा पा रही थी। यह प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी मानी जाने लगी थी। जूलॉजिकल सोसायटी आफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे।

'सेवा और सुशासन के संकल्प के 1.25 लाख द्वीपों से जगमगाया मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला'

''आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने एक साथ प्रज्जवलित किए दीप'

रायपुर। सेवा, समर्पण, सुशासन और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। शाम 7 बजे जिला मुख्यालय सहित जिलेभर के चिन्हित स्थलों पर एक साथ 1.25 लाख द्वीप प्रज्ज्वलित किए गए। दीपों की रोशनी से जिला सेवा, सुशासन, जनकल्याण और जनभागीदारी के सामूहिक संकल्प से जगमगा उठा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा से जुड़े इस आयोजन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। जिला मुख्यालय मोहला के

मिनी स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में करीब 11 हजार दीपों से स्टेडियम जगमगा उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजनांदगांव लोकसभा सांसद श्री संतोष पांडे ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती गैंद कुंवर ठाकुर, जनप्रतिनिधि श्री अनिल गुप्ता, श्री रमेश हिड़ामें, श्री लक्ष्मेंद्र शाह, जिला पंचायत सदस्य श्री नरसिंह भंडारी,कलेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री उज्ज्वल पोरवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्व-सहायता समूह की महिलाएं, शासकीय कर्मचारी, स्कूली बच्चे एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के नक्शे की आकर्षक रंगोली बनाई गई, जो आयोजन का विशेष आकर्षण रही। रंगोली के माध्यम से प्रदेश की एकता और जनभागीदारी का संदेश प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। सांसद श्री संतोष पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की यात्रा है। वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासकीय जिम्मेदारी संभालने के बाद से वे निरंतर जनता की सेवा और देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं।

डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर फंसाया, फिर पुलिसवाला बनकर 2.15 लाख वसूले, दिल्ली पुलिस ने रैकेट का किया पर्दाफाश

नईदिल्ली, एजेंसी। छावला थाना पुलिस ने वसूली के एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसकी महिला सदस्य ने डेटिंग एप के जरिये दोस्ती कर एक शख्स को फरीदाबाद से छावला क्षेत्र के ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाया। यहां पहुंचने पर उसे एक कमरे में ले गई। जहां थोड़ी ही देर बाद पहुंची दो अन्य महिला और पुरुष ने उसे खुद को पुलिसकर्मी बताकर बंधक बना उससे 2.15 लाख रुपये वसूल लिए। पुलिस ने इस मामले में तीनों महिलाओं और उसके पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस दौरान एक महिला ने खुद को पुलिसकर्मी बताया, जबकि उसके पुरुष साथी ने भी खुद को थाने का एसएचओ बताया। आरोपितों के कब्जे से वसूली गई रकम में से 70,500 रुपये बरामद कर लिए हैं। बाकी रकम जिन बैंक खातों में भेजी गई, उन्हें पुलिस ने होल्ड करा दिया है। आरोपितों में सोनीपत निवासी मंदीप (38), गाजियाबाद निवासी प्रीति (32), नजफगढ़ निवासी कमलेश (42) और नजफगढ़ निवासी रितु (40) शामिल है। मंदीप के खिलाफ सोनीपत सिटी थाने में वर्ष 2024 में रंगदारी और धमकी समेत तीन प्राथमिकी और कंझावला थाने में वर्ष 2022 में मारपीट का मामला दर्ज है। कमलेश के खिलाफ द्वारका नार्थ थाने में वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उपायुक्त कुशलपाल सिंह के अनुसार, 14 सितंबर को मथुरा निवासी 44 वर्षीय चंद्रभान सिंह ने थाने में शिकायत दी थी। पीड़ित फरीदाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि क्वैकक्वैक डेटिंग एप के माध्यम से उनकी एक महिला से दोस्ती हुई थी। महिला ने उन्हें ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाया। वहां से उन्हें नजफगढ़ स्थित एक मकान में ले जाया गया। वहां दोनों के पहुंचने के कुछ ही देर बाद अचानक से दो महिला और एक पुरुष पहुंच गए और खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए इसे एक छापामारी बताया और महिला के साथ गलत स्थिति में पकड़े जाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाने की धमकी देकर उनके पास मौजूद 22 हजार रुपये नकदी और अलग-अलग यूपीआई लेन-देन से कुल 2.15 लाख रुपये ले लिए और वहां से चले गए। संदेह होने पर थाने पहुंच शिकायत दी। शिकायत के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। एसीपी जसवंत सिंह की निगरानी और एसएचओ दलीप कुमार के नेतृत्व में एसआइ विकास, पीएसआइ दीक्षा, एचसी जसवंत, सुरेंद्र और कविता की एक टीम गठित की गई। जांच के दौरान मिले तकनीकी और पीड़ित के बताए गए हुलिया के आधार पर पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर चारों को एक एक करके उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया।

सेवा संकल्प अभियान के प्रथम दिवस जशपुर में जगमगाए 5 लाख दीप

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के प्रथम दिवस जशपुर जिले में 'आशीर्वाद का एक दीया' कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, सहभागिता और संकल्प का संदेश शहर से गांव तक पहुंचा। गुरुवार शाम 7 बजे जिले में 5 लाख दीप प्रज्वलित करने के लक्ष्य के साथ आयोजित कार्यक्रम में रणजीता स्टेडियम सहित प्रमुख चौक-चौराहे दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। रणजीता स्टेडियम, गौरव पथ, महाराजा चौक, दिलीप सिंह जूदेव प्रतिमा चौक और बिरसा मुंडा चौक सहित विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने 'आशीर्वाद का एक दीया' प्रज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, सहित जनप्रतिनिधिगण कलेक्टर श्री रोहित व्यास सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। विकासखंडों और ग्राम पंचायतों तक पहुंची दीपों की रोशनी 'आशीर्वाद का एक दीया' कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहा। जिले के सभी विकासखंडों, नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में भी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक दीप प्रज्वलित कर सेवा संकल्प अभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर गांवों तक दीपों की रोशनी ने अभियान को व्यापक जनभागीदारी का स्वरूप दिया। 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने घरों में जलाया दीप जिले के स्व-सहायता समूहों से जुड़ी 1 लाख 40 हजार से अधिक महिला सदस्यों ने अपने घरों में 'आशीर्वाद का एक दीया' जलाकर अभियान में सहभागिता निभाई। जिले में 12 हजार से अधिक स्व-सहायता समूह सक्रिय हैं। कृषि सखी, पशु सखी, मुद्रा लोन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की सहभागिता ने अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। सेवा भावना और जनभागीदारी को मिलेगा विस्तार कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करने और विकसित भारत/2047 के संकल्प को जनभागीदारी के माध्यम से मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न जनभागीदारी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

अभियान के तहत स्कूली बच्चों के लिए भाषण, चित्रकला एवं रंगोली प्रतियोगिताएं,

सेवा, सुशासन और राष्ट्रनिर्माण के संकल्प से जगमगाया जांजगीर-चांपा

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत जांजगीर-चांपा जिले में आज जनभागीदारी के साथ 'आशीर्वाद का दीप' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टोरेट कार्यालय सहित जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों तथा प्रमुख सार्वजनिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों

की रोशनी से जिले के प्रमुख स्थल जगमगा उठे और सेवा, सुशासन, जनकल्याण एवं राष्ट्रनिर्माण के संकल्प का संदेश दिया गया।दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सहभागिता की। दीपों के माध्यम से सेवा एवं समर्पण की भावना के साथ विकसित भारत के संकल्प में जनभागीदारी का संदेश दिया गया। विभिन्न स्थलों पर उत्साहपूर्वक आयोजित कार्यक्रमों ने जिले में सेवा संकल्प अभियान के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित किया। उल्लेखनीय है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक 'सेवा संकल्प अभियान' आयोजित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान सेवा, सुशासन एवं जनकल्याण की

हसदेव नदी के कुदरी बैराज तट पर जगमगाए 'आशीर्वाद का दिया'

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत जांजगीर-चांपा जिले में जनभागीदारी के साथ 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया गया। हसदेव नदी के कुदरी बैराज तट पर सैकड़ों दीपों के प्रज्वलन से पूरा परिसर रोशन हो उठा। दीपों के माध्यम से सेवा, सुशासन, विकास और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण विकसित

भारत 2047 और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े संदेशों को दर्शाती आकर्षक रंगोली रही। रंग-बिरंगे रंगों से सजी रंगोली के मध्य प्रज्वलित 'आशीर्वाद का दीया' ने कार्यक्रम को विशेष स्वरूप दिया। हसदेव नदी के तट पर दीपों की रोशनी और रंगोली के माध्यम से विकास, जनकल्याण और राष्ट्र निर्माण की भावना को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर इंजी. मंजूषा पाटले, श्री सुशील सिंह, श्री सतीश शर्मा, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री सुधीर सुखदेव, तहसीलदार श्री शशिभूषण सोनी, एसडीओ श्री रविकांत तथा ग्राम पंचायत कुदरी के सरपंच प्रतिनिधि श्री आर.के. यादव सहित अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

2027 की तैयारियों में जुटी आप, पंजाब में घर-घर पहुंचेगा संगठन

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में किए गए कामों और योजनाओं को लेकर सीधे लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। इसके तहत 20 सितंबर से प्रदेशभर में बड़े स्तर पर डोर-टू-डोर अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़े नेता भी घर-घर जाकर लोगों से संवाद करेंगे और मान सरकार के कामकाज की जानकारी देंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी पंजाब के लोगों के बीच जाकर सरकार के कामों को रखेगी। उन्होंने दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में लोगों से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने मान सरकार पर भरोसा जताया है और सरकार के कामों से लोग खुश हैं। सिसोदिया ने कहा कि पंजाब की जवानी को बचाने के लिए सरकार ने नशे के खिलाफ कई स्तर पर काम किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सिसोदिया ने पिछली सरकारों पर पंजाब में नशा फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि आप सरकार का फोकस युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पर है।

शिक्षा को भी बनाया जाएगा मुद्दा: उन्होंने कहा कि सरकार के कामों को लेकर केवल राजनीतिक मंचों पर चर्चा करने के बजाय अब पार्टी कार्यकर्ता सीधे लोगों के घरों तक पहुंचेंगे। इस दौरान नौजवानों, व्यापारियों, महिलाओं और अन्य वर्गों से बातचीत की जाएगी। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि इन वर्गों में सरकार के कामकाज को लेकर संतुष्टि है। सिसोदिया ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों को भी अभियान का प्रमुख मुद्दा बताया।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर जगमगाया लखनऊ, राष्ट्र प्रेरणा स्थल' पर एक साथ जले साढ़े तीन लाख दीये

लखनऊ, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 76वां जन्मदिवस राजधानी में यादगार बन गया। बारिश के बाद भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल में साढ़े तीन लाख दीये शाम होते ही जगमगा उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम व सेवा संकल्प के तहत पंडित दीन दयाल उपाध्याय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं पर दीप जलाकर अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद किया। मोबाइल से वीडियो बनाया और वहां मौजूद छात्रों को चाकलेट दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनके स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश को विकसित भारत की संकल्पना की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। देशभर में करोड़ों दीप सकारात्मक भाव और ऊर्जा के

साथ प्रज्वलित हो रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल ही नहीं प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घरों में भी दीप जलाए जा रहे हैं। उन्होंने अभियान से जुड़े कर्मयोगी कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों और नागरिकों का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि व प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का शिल्पी बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश ने अपनी नई पहचान बनाई है और नए भारत का दर्शन हो रहा है। हर क्षेत्र के व्यक्ति को इस बदलाव पर गौरव की अनुभूति हो सकती है। भारत आज नई पहचान, नए इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक तकनीक में नेतृत्व देने वाले देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीएम को देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करने वाला बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। यहां उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सदस्य बृजलाल, विधान परिषद सदस्य डॉ. लाल जी निर्मल, विधान परिषद सदस्य डॉ. अविनाश सिंह, विधायक डॉ. नीरज बोरा, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार व सचिव सुशील प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।

प्रेरणा स्थल का लोगो व राम मंदिर की बनी आकृति

समारोह में शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं व स्वयंसेवकों सहित लगभग 10 हजार प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जयपुरिया कालेज, गोयल इंस्टीट्यूट आफ हायर स्टडीज, डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के छात्र-छात्राओं एवं वालंटियर्स ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रेरणा स्थल को 59 सेक्टर में बांटा गया था। 11 घंटे की मेहनत से 5000 मीटर लंबी दीप श्रृंखला बनायी गयी। वहीं, मुख्य मंच के पास 19 हजार दीयों की साज-सज्जा से एलडीए व राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोगो और राम मंदिर की आकर्षक आकृति बनायी गयी।

दूरदराज क्षेत्रों तक हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता : वी. श्रीनिवास

जयपुर, एजेंसी। शासन सचिवालय में शुक्रवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 18वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेशभर में डिजिटल बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना 2026-27 के तहत किए जाने वाले सुधारों, दूरसंचार राइट ऑफ वे नियम-2024 के क्रियान्वयन एवं 4जी सेचुरेशन परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के दूरदराज, जनजातीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों (वाइब्रेंट विलेज) तक डिजिटल सेवाओं व निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के अभाव में आमजन को सरकारी योजनाओं व डिजिटल सेवाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। आर ओ डब्लू सुधारों व सिंगल विंडो सिस्टम को गति देने के निर्देश–मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी नए आर ओ डब्लू नियमों को राज्य के सभी नगरीय निकायों, निगमों व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अंगीकृत किया जाए। बैठक में बताया गया कि 7 प्रमुख विभाग पहले ही राज्य आर ओ डब्लू पोर्टल से जुड़ चुके हैं तथा शेष संस्थाओं का एकीकरण भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑफलाइन आवेदनों की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर सभी प्रक्रियाएं स्टेट आर ओ डब्लू पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी ढंग से संचालित हों।बैठक के दौरान बताया गया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की विशेष सहायता योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के सभी बकाया आर ओ डब्लू आवेदनों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने आर ओ डब्लू अनुमतियों के औसत निस्तारण समय को 45 दिन से कम (वर्तमान औसत लगभग 32 दिन) बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया तथा शेष औपचारिकताओं यथा संशोधित भारतनेट परियोजना एडेंडम का निष्पादन एवं ऊर्जा विभाग द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म व समेकित बिलिंग व्यवस्था को समयबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य को 150 करोड़ रुपए की संपूर्ण प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सके।

भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा कदम, रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों को दोबारा उसी जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी : एसीबी प्रमुख चावला

चंडीगढ़ , एजेंसी। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने महत्वपूर्ण पहल की है। एसीबी प्रमुख अरशिंदर सिंह चावला ने बताया कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भविष्य में उसी जिले में दोबारा पोस्टिंग न देने के संबंध में सभी संबंधित सरकारी विभागों को पत्र लिखा गया है। यह निर्णय एसीबी की हाई पावर कमेटी में विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और इसे जल्द लागू किया जाएगा। चावला ने कहा कि कई बार ऐसा देखने में आया कि किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होने के बाद कुछ समय पश्चात उसकी दोबारा उसी जिले में पोस्टिंग हो जाती थी। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के उद्देश्य और आमजन के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए एसीबी की हाई पावर कमेटी में इस मुद्दे पर चर्चा की गई और सरकार के समक्ष आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। अब सभी सरकारी विभागों को पत्र भेजकर ऐसे मामलों में उसी जिले में दोबारा पोस्टिंग से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। - *वर्ष 2026 में अब तक 138 सफल ट्रैप कार्रवाई*एसीबी प्रमुख ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 138 सफल ट्रैप कार्रवाई की जा चुकी हैं, जिनमें सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि आमजन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आ रहा है और एसीबी की कार्रवाई व्यवस्था पर उसका विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी अवकाशों को अलग कर देखा जाए तो औसतन लगभग हर दूसरे दिन एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंकड़ा केवल कार्रवाई की संख्या नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोग भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए आगे आ रहे हैं।एसीबी प्रमुख ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से अब तक 21 मामलों में 23 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहती, बल्कि एसीबी द्वारा मामलों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाते हुए दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई केवल तत्काल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण तक प्रभावी पैरवी और फॉलोअप सुनिश्चित किया जा रहा है।

जन भवन में बालिकाओं का हुआ एचपीवी टीकाकरण

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा से माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर आज जन भवन में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की 100 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर महादेव बोबडे की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। लखनऊ स्थित विभिन्न विद्यालयों से आई बालिकाओं ने इस टीकाकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉ. बोबडे ने बालिकाओं से संवाद कर उनका कुशल-क्षेम पूछा तथा एचपीवी टीकाकरण की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एचपीवी टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर से बचाव की दिशा में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पूर्व सुरक्षा है। उन्होंने बताया कि माननीय राज्यपाल महोदया की प्रेरणा से इस दिशा में पहल की गई और आज यह अभियान देशभर में संचालित हो रहा है। उन्होंने बालिकाओं को टीके से संबंधित जानकारी दी तथा कहा कि लंबे समय के शोध एवं अनुसंधान के बाद विकसित यह

टीका उन्हें सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए इस प्रकार के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आज के कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की सराहना करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई दी।

टीकाकरण के उपरांत सभी बालिकाओं को फल के पैकेट एवं प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। डॉ. बोबडे ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि टीकाकरण कराने वाली बालिकाओं में पोषण की दृष्टि से कमजोर बालिकाओं को चिन्हित कर उनकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग कराई जाए तथा उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों से संवाद कर उन्हें आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बालिकाओं को जन भवन परिसर का भ्रमण कराने के भी निर्देश दिए, ताकि वे परिसर की विभिन्न गतिविधियों एवं नवाचारों से परिचित हो सकें।

कार्यक्रम में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. पिंकी जोवल, महानिदेशक, परिवार कल्याण, डॉ. शुभा मिश्रा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं चिकित्सकीय टीम तथा जन भवन के अधिकारी व कर्मचारीगण, क्षय रोगी व अभिभावकगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

आश्रय से आगे, अधिकार तक

लखनऊ, एजेंसी। वृद्धजनों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वृद्धाश्रमों में उन्हें केवल आश्रय नहीं, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिले, इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हर पात्र वृद्धजन तक उनका अधिकार पहुंचे और वह गरिमा और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। असीम अरुण समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वृद्धजनों को सिर्फ एक सुरक्षित छत ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने पर समाज कल्याण विभाग विशेष जोर दे रहा है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के वृद्धाश्रमों में रह रहे वृद्धजनों को उनकी पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सहित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विभाग की यह पहल वृद्धजनों को आश्रय के साथ सामाजिक सुरक्षा का संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। उपनिदेशक एवं योजनाधिकारी आर पी सिंह ने बताया कि प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 75 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 6,607 बुजुर्ग निवासरत हैं, जिनमें से 4,901 पात्र वृद्धजनों वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 2,551 बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा-न्होंने बताया कि आर्थिक सुरक्षा के साथ बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पात्र 2,551 बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। वृद्धाश्रमों में निवासरत संवासियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है। साथ ही पात्र महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। दो वित्तीय वर्षों में 1,073 नए बुजुर्ग योजनाओं से जुड़े-विभाग द्वारा बुजुर्गों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ देने के लिए समय-समय पर जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में इन योजनाओं के अंतर्गत कुल 1,073 नए बुजुर्गों को जोड़ा गया है।

विज्ञान नगरी में धूमधाम से मनाया गया अर्न्तराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस

लखनऊ, एजेंसी। राजधानी के अलीगंज स्थित आंचलिक विज्ञान नगरी में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उ0प्र0 तथा विज्ञान नगरी के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय अर्न्तराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस बड़ी ही धूमधाम से आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजधानी के विभिन्न विद्यालयों के आठ सौ से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने विज्ञान नगरी का भ्रमण किया। विज्ञान नगरी के शिक्षा अधिकार विकास ने बताया कि समापन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर नवीन अरोडा उपस्थित थें। उन्होने ओजोन परत संरक्षण की उपयोगिता परप प्रकाश डालते हुये रोचक व्याख्यान भी दिया। इस अवसर पर प्रायोजित कार्यक्रम के तहत राजकीय विद्यालयों के बच्चों ने भी भाग लिया। साथ ही इस अवसर पर दो दिनों में स्कूली बच्चों के लिए क्विज पोस्टर मेंकिंग स्लोगन राइटिंग तथा एक्सटेंपोर जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के साथ विज्ञान नगरी के परियोजना समन्वयक स्वरूप् मंडल ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शील्ड, मेंडल, प्रमाणपत्र तथा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, निलम्बित

लखनऊ, एजेंसी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर को, जिनके विरुद्ध विभिन्न आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है, को उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उ.प्र. सरकारी सेवक नियमावली, 1999 के नियम-4 के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।निलम्बन की अवधि में श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे। शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में कहा गया है कि अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर द्वारा कार्यालय के अधीनस्थ कार्मिकों के साथ आपत्तिजनक आचरण / व्यवहार करने के कारण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, शासन तथा प्रशासन की छवि धूमिल करने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने, शासकीय पद की गरिमा के विपरीत आचरण करने एवं अपेक्षित अनुशासन का पालन न करने आदि पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये हैं।

चार मेडिकल कॉलेजों में 73 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सीटों पर बढ़ाए गए आरक्षण कोटे पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को कहा कि इन कॉलेजों में नीट-यूजी काउंसिलिंग अन्य कॉलेजों में लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ही जारी रहेगी। याचियों ने राज्य सरकार के एक सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए बताया था कि इससे करीब 73 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई हैं। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश सचिन सिंह व एक अन्य की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि अंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन के मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण कोटा बढ़ाकर काउंसिलिंग कराई जा रही है, जो कानून की मंशा के खिलाफ है। कोर्ट ने इन कालेजों में बढ़े आरक्षण कोटे पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल अन्य कालेजों में निर्धारित आरक्षण (एससी के लिए 21 प्रतिशत, एसटी के लिए 2 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत) के समान ही इन कालेजों में भी काउंसिलिंग कराएं। इससे पहले 14 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक व चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को रिकॉर्ड के साथ 16 सितंबर को तलब किया था। हालांकि, मामले में विस्तृत आदेश अभी नहीं आया है।

रालोद राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे का जन्मदिन समारोह आयोजित

लखनऊ। रालोद के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय लोकदलकेंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य अनिल दुबे का जन्मदिन समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल द्वारा किया गया।समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक शिवकरण सिंह ने की। इस अवसर पर युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल, प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल तथा श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर की गरिमामयी उपस्थिति रही।प्रदेश कोषाध्यक्ष बी0 एल0 प्रेमी, रामवती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, चंद्रकांत अवस्थी, अंकुर सक्सेना, अफसर अली, सम्राट सिंह चौहान, गणेश प्रसाद, सुमित सिंह, रमेश कश्यप, अनुराग जाट, छाया सिंह लोधी, पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेकार्यक्रम के दौरान उपस्थित पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अनिल दुबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

शिया पी.जी. कॉलेज में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अयातुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही का हुआ अभिनंदन

लखनऊ, एजेंसी। शिया पी.जी. कॉलेज, लखनऊ में भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अयातुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कॉलेज प्रबंधन, शिक्षकगण तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक मूल्यों तथा भारत और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर विचार व्यक्त किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए अयातुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने शिया पी.जी. कॉलेज में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की और शिक्षा तथा समाज के क्षेत्र में संस्थान के लंबे योगदान की सराहना की। भारत में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया और उन्होंने भारत सरकार द्वारा इसकी मेजबानी के लिए आभार व्यक्त किया। शिया पी.जी. कॉलेज के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संस्थान के बारे में काफी सुना है और पिछले 108 वर्षों में समाज के लिए इसके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह कॉलेज केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यहां शिक्षा, इतिहास

और संस्कृति एक साथ दिखाई देते हैं। उन्होंने लखनऊ को शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए भारतीय संस्कृति में शहर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि शिया पी.जी. कॉलेज और लखनऊ का इतिहास एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। कॉलेज की बहुसंस्कृति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न धर्मों से जुड़े शिक्षक बिना किसी भेदभाव के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने इस विविधता को समाज के विकास और उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए हकीम इलाही ने कहा कि शिया समुदाय का ज्ञान और शिक्षा के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान आगा बुजुर्ग तेहरानी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने शिया विद्वानों और समाज के सभ्यतागत विकास में योगदान को दस्तावेजीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि संस्थाएं और समुदाय केवल अपने गौरवशाली इतिहास पर निर्भर होकर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने शिक्षा के निरंतर विकास और प्रसार की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें केवल अपने अतीत पर गर्व करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों और संस्थान से जुड़े लोगों से यह विचार करने का आह्वान किया कि जिस प्रकार पूर्वजों ने शिक्षा के विकास के लिए कार्य किया, उसी प्रकार वर्तमान पीढ़ी शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण निरंतर प्रयासों से ही संभव है। हकीम इलाही ने सुझाव दिया कि शिया पी.जी. कॉलेज की पहचान केवल धार्मिक संस्था तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे सामाजिक विकास और संवाद के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी स्थापित होना चाहिए।

400 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, निपुणता का इम्तिहान नवंबर में

लखनऊ, एजेंसी। जिन कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक कम हैं, उन्हीं कक्षाओं में नवंबर में बच्चों की निपुणता परखी जाएगी। राजधानी के 400 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। वहीं 2000 से अधिक शिक्षक पिछले काफी समय से बीएलओ ड्यूटी में लगे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद 1200 से अधिक परिषदीय स्कूलों में बालवाटिका से कक्षा तीन तक के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को निपुण आकलन में शामिल करने की तैयारी है। नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात सही नहीं है। ऐसे में बच्चों की नियमित पढ़ाई के बीच नवंबर में होने वाला निपुण आकलन विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। आकलन की रूपरेखा को लेकर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। निपुण भारत मिशन के तहत बालवाटिका से कक्षा तीन तक बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) का आकलन 75 फीसदी सटीकता के मानक पर किया जाता है। विद्यार्थी को निपुण तब माना जाता है, जब वह अपनी कक्षा के निर्धारित भाषा और गणित की दक्षताओं से जुड़े कम से कम 75 फीसदी प्रश्नों के सही उत्तर देता है। (संवाद)भाषा से गणित तक परखी जाएगी दक्षताः बालवाटिका और आंगनबाड़ी स्तर पर दो-तीन अक्षर वाले सरल शब्द पढ़ने, अपने नाम की पहचान, एक से नौ तक की संख्याओं की पहचान, लेखन और गणना की क्षमता परखी जाएगी।कक्षा एक में चार से पांच सरल शब्दों वाले वाक्य पढ़ने तथा 20 तक की संख्याओं की पहचान, एक-अंकीय जोड़ और घटाव का आकलन होगा।कक्षा दो में छह से आठ वाक्यों के अज्ञात पाठ को स्पष्टता से पढ़कर 75 फीसदी प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। साथ ही 99 तक की दो-अंकीय संख्याओं का जोड़-घटाव हल करना होगा।कक्षा तीन में आठ से दस वाक्यों के अज्ञात अनुच्छेद को समझकर पढ़ने और 75 फीसदी प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे।

प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर शाहगंज में 'सेवा संकल्प अभियान' का

लखनऊ, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को जनपद जौनपुर की शाहगंज तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 'सेवा संकल्प अभियान' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सेवा, जनकल्याण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए विभिन्न जनसेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले नागरिकों का उत्साहवर्धन करते हुए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर मिला रक्त उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच अंतर बन सकता है। दुर्घटना, गंभीर बीमारी, प्रसव अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में रक्त की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का ऐसा कार्य है, जिसमें प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों में जनसेवा को राष्ट्रसेवा का माध्यम बनाया है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और

जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा सेवा की भावना को जनभागीदारी से जोड़ना प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन की प्रमुख प्रेरणाओं में रहा है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' इसी सेवा भाव को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शाहगंज में रक्तदान के माध्यम से लोगों ने सेवा और संवेदना का जो संदेश दिया है, वह समाज के लिए प्रेरणादायी है। सेवा केवल किसी एक व्यक्ति या संस्था का दायित्व नहीं है, बल्कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है, तभी जनसेवा का भाव जनआंदोलन का रूप लेता है।

जैव विविधता और इको-टूरिज्म से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा रिजर्व टाइगर संरक्षण

लखनऊ, एजेंसी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज बाघ संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन और इको-टूरिज्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान बना रहा है। वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के प्रयासों ने इस क्षेत्र को संरक्षण के एक प्रभावी मॉडल के रूप में स्थापित किया है। इसी दिशा में पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है।प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने और फाउंडेशन के कार्यों की समीक्षा के उद्देश्य से 09 सितंबर, 2026 को वन विभाग मुख्यालय स्थित पारिजात कक्ष में पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन के शासी निकाय की तृतीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासी निकाय की पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 के लिए प्रस्तावित दरों तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में फाउंडेशन के पास उपलब्ध धनराशि के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बेहतर प्रबंधन, पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार और संरक्षण गतिविधियों को प्रभावी बनाने से जुड़े प्रस्तावों को शासी निकाय ने मंजूरी प्रदान की। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम प्राथमिकता-प्रदेश सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए विशेष व्यवस्था की है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाली आबादी और वन्यजीवों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बाघों और अन्य वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों के बीच मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार निगरानी और जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित ग्रामवासियों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार किया जा रहा है। शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं और सहायता पीड़ित परिवारों को तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि संकट की स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

जन भवन में 76 टी.बी. रोगियों को गोद लेकर वितरित की गई पोषण पोटली

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में जन भवन, में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 76 वें जन्मदिवस के अवसर पर 'निक्षय मित्र' पहल के अंतर्गत जन भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सुरक्षाकर्मियों द्वारा 76 टी.बी. रोगियों को गोद लिया गया तथा उन्हें पोषण पोटली वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबडे द्वारा की गयी। कार्यक्रम में टी.बी. उन्मूलन, उसकी रोकथाम, बचाव, समय पर जांच एवं उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा राज्यपाल महोदया द्वारा टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर राज्यपाल महोदया का संबोधन उनके विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े द्वारा पढ़कर सुनाया गया। राज्यपाल महोदया ने अपने संबोधन में भगवान विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का

दिन दो कारणों से विशेष है। एक ओर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा-अर्चना का अवसर है, वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 76वां जन्मदिवस है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्माजी को सृजन, निर्माण, शिल्प, वास्तु और तकनीकी कौशल का प्रतीक माना गया है। हमारी संस्कृति ने सदैव श्रम को सम्मान दिया है। कार्यक्रम में विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े ने कहा कि टी.बी. उन्मूलन के लिए रोगियों की नियमित निगरानी और उपचार की निरंतरता पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से ऐसे मरीज, जिन्हें दोबारा टी.बी. हुई है, उनके उपचार, जांच और स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित निगरानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों की पहचान कर उन्हें समय से उपचार उपलब्ध कराने तथा उपचार पूरा होने तक आवश्यक सहयोग प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ.प्र. डॉ. शुभा मिश्रा ने कहा कि टीबी का इलाज संभव है। इसके लिए समय पर जांच, नियमित दवा, संतुलित आहार तथा अतिरिक्त पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीबी मरीज का अधिकार केवल दवा ही नहीं, बल्कि पोषण और प्यार भी है। मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉ. पिंकी जोवल ने स्वच्छता, पौष्टिक खान-पान, पर्याप्त पोषण और नियमित योगाभ्यास को स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए इन आदतों को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 'टीबी हारेगा, तभी देश जीतेगा और देश तभी जीतेगा, जब उत्तर प्रदेश जीतेगा।' महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ.प्र., डॉ. पवन कुमार अरुण ने 'सेवा संकल्प अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समय पर जांच और नियमित रूप से दवा लेने से टीबी को हराया जा सकता है। सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, डॉ. पिंकी जोवल ने कहा कि टी.बी. लाइलाज बीमारी नहीं है। यदि समय रहते इसकी पहचान हो जाए तो इसका उपचार संभव है। उन्होंने कहा कि पहले उपचार एवं जांच में काफी समय लगता था, लेकिन अब टीबी की जांच, डायग्नोसिस, बलगम जांच तथा आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।